

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्मूल पहाडिया आई.ए.एस.

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा

-

प्रार्थी

बनाम

श्री त्रिलोक चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इनायती तहसील सपोटरा जिला करौली

-

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सीज्ड किये गये 97.30 क्विं. गेहूँ एवं 1237.50 लीटर केरोसीन को राजसात् करने बाबत


निर्णय

दिनांक 24.05.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले के भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जाँच दल द्वारा श्री त्रिलोक चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इनायती तहसील सपोटरा की दिनांक 13.05.2017 से 14.05.2017 तक जाँच की गई जिसमें निम्न अनियमिततायें पायी गयीं—

1. वक्त जाँच उचित मूल्य दुकान बन्द मिली, दुकान पर डीलर उपस्थित नहीं मिला, दुकान बन्द होने का दुकान पर कोई कारण अंकित नहीं मिला, दुकान पर उचित मूल्य दुकान का टाईटल बोर्ड प्रदर्शित नहीं करना।
2. मौके पर उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर द्वारा माह अप्रैल 17 के गेहूँ का वितरण नहीं करना, निर्धारित स्थल पर राशन सामग्री का भण्डारण नहीं करना, स्टॉक मूल्य एवं वितरण मात्रा का प्रदर्शन नहीं करना।
3. सितम्बर 16 और उससे पहले के गेहूँ, चीनी व केरोसीन तेल के वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करना, केरोसीन तेल का सितम्बर 16 का वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करना, पोश मशीन से वितरण किये गये वितरण का प्रिन्ट दुकान पर नहीं रखना, मासिक नक्शों प्रस्तुत नहीं करना।
4. डीलर की दुकान पर सितम्बर 16 से वक्त जाँच दिनांक 14.05.2017 तक 426.25 क्विं. गेहूँ की आपूर्ति की गई जिसमें से अप्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में 388.30 क्विंटल गेहूँ वितरित कर दिया। अतः डीलर के पास 37.95 क्विंटल गेहूँ होना चाहिए था जबकि उसके पास भौतिक सत्यापन पर 97.30 क्विंटल गेहूँ मिला। इस प्रकार डीलर के पास 59.35 क्विंटल गेहूँ अधिक मिला। उक्त समस्त 97.30 क्विं. गेहूँ मय बारदाना को श्रीमति उच्छो देवी जोगी पत्नि श्री नथुआ लाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत हरिया का मन्दिर केन्द्र बलुआपुरा तहसील सपोटरा को सुपुदगी में दिया गया।
5. डीलर के द्वारा 1237.5 लीटर केरोसीन तेल का अनाधिकृत स्थल पर भण्डारण किया गया है। उक्त समस्त 1237.5 लीटर केरोसीन तेल मय 6 खडे लोहे के ड्रम जो कि रिसाव रहित हैं, को श्रीमति उच्छो देवी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत हरिया का मन्दिर तहसील सपोटरा के कार्यकर्ता श्री हरसहाय जोगी पुत्र श्री नथुआ निवासी बलुआपुरा तहसील सपोटरा को सुपुदगी में दिया गया।

इस प्रकार जांच दल द्वारा दिनांक 13.05.2017 से 14.05.2017 तक श्री त्रिलोक चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इनायती 1/3 भाग तहसील सपोटरा की जाँच की गई। डीलर द्वारा उक्त अनियमिततायें कारित कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के खण्ड 3 तथा इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों 6, 8, 9, 11, 17सी व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है एवं पीडीएस ऑर्डर 2015, एनएफएसए 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जप्तशुदा 97.30 क्विंटल गेहूँ मय बारदाना एवं 1237.50 लीटर केरोसीन तेल मय 6 खडे लोहे के ड्रम


जिला कलक्टर
करौली

जो कि रिसाव रहित है, को राजसात करने एवं जब्तशुदा केरोसीन एवं गेंहू का अंतरिम निस्तारण करने का निवेदन किया हैं

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र का मद नं. 1 जिस तौर पर दर्ज है में प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान बन्द पाई गयी होना, दुकान बन्द होने का दुकान पर कोई कारण अंकित नहीं करना, दर्ज किया है जिससे स्पष्ट साबित होता है कि अप्रार्थी की दुकान का एवं गोदाम का कोई निरीक्षण जांच दल द्वारा दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 तक नहीं किया गया है जबकि अप्रार्थी की दुकान पर उचित मूल्य दुकान का टाईटल बोर्ड प्रदर्शित था, दुकान खुली हुयी थी, तब दुकान बन्द होने का कोई कारण लिखने का अंकित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 15.05.2017 तक जांच दल खाद्य विभाग द्वारा जयपुर द्वारा गठित कर रवाना नहीं किया गया है। दिनांक 14.05.2017 की या 15.05.2017 को अप्रार्थी की दुकान व गोदाम का निरीक्षण जांच दल द्वारा नहीं किया गया है। यह सारे तथ्य गलत दर्ज किये है जो अप्रार्थी को स्वीकार नहीं है। प्रार्थनापत्र का मद नं. 2 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा माह अप्रैल 2017 के गेंहू का उपभोक्ताओं को पोश मशीन से वितरण किया गया है। किसी उपभोक्ता द्वारा शिकायत नहीं की गयी है। राशन सामग्री गोदाम व दुकान पर ही रखी हुयी थी। स्टॉक मूल्य एवं वितरण मात्रा रजिस्टर व पोश मशीन में रही है जिसका प्रदर्शन टाईटल बोर्ड में अंकित रहा है। कोई फोटो प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे दुकान बन्द होना साबित होता हो एवं टाईटल बोर्ड का प्रदर्शन नही होना, निर्धारित स्थल पर राशन सामग्री नहीं रखना साबित होता हो। मात्र कयास के तौर पर सारे तथ्य वेग व निराधार एवं झूठे प्रार्थनापत्र में राजनैतिक द्वेषता से प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक ने असर में आकर दर्ज किये है जिनसे अप्रार्थी के विक्रय कोई अपराध घटित नहीं होता है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी की दुकान व गोदाम का जांच दल द्वारा निरीक्षण व जांच नही की गयी है तब अप्रार्थी द्वारा सितम्बर 2016 और उससे पहले के गेंहू, चीनी व केरोसीन तेल के वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नही करने एवं केरोसीन तेल का सितम्बर 2016 का वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने का पोश मशीन से वितरण किये गये वितरण का प्रिन्ट दुकान पर नहीं रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मासिक नक्शे प्रस्तुत नही करने का कोई नोटिस प्रार्थी ने अप्रार्थी को नही दिया है। अप्रार्थी मासिक नक्शे समय-समय पर प्रार्थी व प्रार्थी के कार्यालय में प्रस्तुत करता रहा है। यह समस्त तथ्य गलत तौर पर निराधार इस मद में दर्ज किये है, जिनसे अप्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराध गठित नहीं होता है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। सितम्बर 2016 में राशन सामग्री का वितरण गेंहू व केरोसीन का वितरण रजिस्टर से सम्पूर्ण जिला करौली में हुआ है। इसके बाद माह अक्टूबर 2016 से दिनांक 15.05.2017 यानि माह अप्रैल मई 2017 तक वितरण गेंहू व केरोसीन का पोश मशीन से किया गया है। इन समस्त तथ्यों को प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा इस मद में जानबूझ कर छुपाया गया है। माह सितम्बर 2016 की राशन सामग्री स्टॉक रजिस्टर में शेष रही है एवं वितरण की गयी है, को जांच रिपोर्ट में दर्ज नही किया गया है। मात्र पोश मशीन के वितरण के आधार पर यह सारी कार्यवाही को राजनैतिकवश अंजाम दिया गया है। दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 14.05.2017 के कोई फर्दमौका पर्चा तैयार नही किये गये है। सारी कार्यवाही गलत रूप से तैयार की गयी है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी व अनियमितता नहीं की गयी है। प्रार्थनापत्र का मद नं. 5 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। माह सितम्बर 2016 में राशन सामग्री गेंहू व केरोसीन का वितरण जिला करौली में वितरण रजिस्टर से किया गया है। जिसके तहत केरोसीन का सितम्बर 2016 का वितरण, वितरण रजिस्टर से हुआ है। जिसे मद में प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जानबूझकर दर्ज नही किया गया है। यदि सितम्बर 2016 के स्टॉक व वितरण रजिस्टर के तहत सामग्री को मात्रा से आंकलन कर दर्ज किया जाता तब अप्रार्थी के विक्रय कोई अनियमितता नही पायी जाती परन्तु राजनैतिक रंजिश के कारण इस

तथ्य को छुपाकर यह गलत तथ्यों पर आवेदन पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी के विरुद्ध प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 112/2017 थाना सपोटरा धारा 3/7 ई.सी.एक्ट 'माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एसबी क्रीमिनल रिट पिटीशन न. 5871/2017 के निर्णय दिनांक 06.03.2018 से निरस्त की जा चुकी है। जिसकी प्रमाणित प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत है एवं अप्रार्थी के विरुद्ध की गयी जांच रिपोर्ट दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 15.05.2017 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के सिविल रिट याचिका संख्या 12858/2017 निर्णय दिनांक 09.08.2017 से निरस्त की जा चुकी है एवं राज्य सरकार द्वारा दायर द्वितीय सिविल स्पेशल अपील मु.नं. 1647/17 दिनांक 04.12.2017 को खारिज हो चुकी है। इन समस्त निर्णयों से अप्रार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 113/17 निरस्त हो जाने से दिनांक 15.05.2017 को तैयार किया गया सुपुर्दगीनामा की समस्त सामग्री अप्रार्थी को वापस लौटाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अप्रार्थी के विरुद्ध दण्डक कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है तब समस्त रसद सामग्री (जब्तशुदा) अप्रार्थी के वापस लौटाई जाये। निर्णय दिनांक 09.08.2017 व 04.12.2017 की फोटो प्रति जवाब के साथ पेश की है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 निरस्त किया जाकर दिनांक 15.05.2017 को अभिग्रहण व सुपुर्द की गयी समस्त सामग्री गेहू व केरोसीन अप्रार्थी के वापिस लौटाये जाने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले के भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जांच दल द्वारा श्री त्रिलोक चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इयानती तहसील सपोटरा की दिनांक 13.05.2017 से 14.05.2017 तक जांच की गई जिसमें वक्त जांच उचित मूल्य दुकान बन्द मिली, दुकान पर डीलर उपस्थित नहीं मिला, दुकान बन्द होने का दुकान पर कोई कारण अंकित नहीं मिला, दुकान पर उचित मूल्य दुकान का टाईटल बोर्ड प्रदर्शित नहीं करना पाया गया। मौके पर उपभोक्ताओ ने बताया कि डीलर द्वारा माह अप्रैल 17 के गेहू का वितरण नहीं करना, निर्धारित स्थल पर राशन सामग्री का भण्डारण नहीं करना, स्टॉक मूल्य एवं वितरण मात्रा का प्रदर्शन नहीं करना पाया गया। सितम्बर 16 और उससे पहले के गेहू, चीनी व केरोसीन तेल के वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करना, केरोसीन तेल का सितम्बर 16 का वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करना, पोश मशीन से वितरण किये गये वितरण का प्रिन्ट दुकान पर नहीं रखना, मासिक नक्शें प्रस्तुत नहीं करना पाया गया। डीलर की दुकान पर सितम्बर 16 से वक्त जांच दिनांक 14.05.2017 तक आपूरित 426.25 क्विं. गेहू में से 388.30 क्विंटल गेहू वितरित कर दिया। अतः डीलर के पास 37.95 क्विंटल गेहू होना चाहिए था जबकि उसके पास भौतिक सत्यापन पर 97.30 क्विंटल गेहू मिला। इस प्रकार डीलर के पास 59.35 क्विंटल गेहू अधिक मिला। उक्त समस्त 97.30 क्विं. गेहू मय बारदाना जब्त किया गया। डीलर के द्वारा 1237.5 लीटर केरोसीन तेल का अनाधिकृत स्थल पर भण्डारण किया गया है। उक्त समस्त 1237.5 लीटर केरोसीन तेल मय 6 खडे लोहे के ड्रम जो कि रिसाव रहित हैं, को जब्त किया गया। अंत में जब्तशुदा 97.30 क्विंटल गेहू मय बारदाना एवं 1237.50 लीटर केरोसीन तेल मय 6 खडे लोहे के ड्रम जो कि रिसाव रहित है, को राजसात् करने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी की दुकान पर उचित मूल्य दुकान का टाईटल बोर्ड प्रदर्शित था, दुकान खुली हुयी थी, तब दुकान बन्द होने का कोई कारण लिखने का अंकित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 15.05.2017 तक जांच दल खाद्य विभाग द्वारा जयपुर द्वारा गठित कर रवाना नहीं किया गया है। दिनांक 14.05.2017 की या 15.05.2017 को अप्रार्थी की दुकान व गोदाम का निरीक्षण जांच दल द्वारा नहीं किया गया है। यह सारे तथ्य गलत दर्ज किये है जो अप्रार्थी को स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा माह


जिला कलक्टर
जयपुर

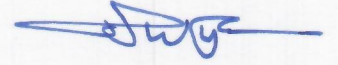
अप्रैल 2017 के गेहू का उपभोक्ताओं को पोश मशीन से वितरण किया गया है। किसी उपभोक्ता द्वारा शिकायत नहीं की गयी है। राशन सामग्री गोदाम व दुकान पर ही रखी हुयी थी। स्टॉक मूल्य एवं वितरण मात्रा रजिस्टर व पोश मशीन में दर्ज रही है जिसका प्रदर्शन टाईटल बोर्ड में अंकित रहा है। कोई फोटो प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे दुकान बन्द होना साबित होता हो एवं टाईटल बोर्ड का प्रदर्शन नहीं होना, निर्धारित स्थल पर राशन सामग्री नहीं रखना साबित होता हो। मात्र कयास के तौर पर सारे तथ्य वेग व निराधार एवं झूठे प्रार्थनापत्र में राजनैतिक द्वेषता से प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक ने असर में आकर दर्ज किये है जिनसे अप्रार्थी के विक्रय कोई अपराध घटित नहीं होता है। अप्रार्थी की दुकान व गोदाम का जांच दल द्वारा निरीक्षण व जांच नहीं की गयी है तब अप्रार्थी द्वारा सितम्बर 2016 और उससे पहले के गेहू, चीनी व केरोसीन तेल के वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने एवं केरोसीन तेल का सितम्बर 2016 का वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने का पोश मशीन से वितरण किये गये वितरण का प्रिन्ट दुकान पर नहीं रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मासिक नक्शे प्रस्तुत नहीं करने का कोई नोटिस प्रार्थी ने अप्रार्थी को नहीं दिया है। अप्रार्थी मासिक नक्शे समय-समय पर प्रार्थी व प्रार्थी के कार्यालय में प्रस्तुत करता रहा है। यह समस्त तथ्य गलत तौर पर निराधार इस मद में दर्ज किये है, जिनसे अप्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराध गठित नहीं होता है। सितम्बर 2016 में राशन सामग्री का वितरण गेहू व केरोसीन का वितरण रजिस्टर से सम्पूर्ण जिला करौली में हुआ है। इसके बाद माह अक्टूबर 2016 से दिनांक 15.05.2017 यानि माह अप्रैल मई 2017 तक वितरण गेहू व केरोसीन का पोश मशीन से किया गया है। इन समस्त तथ्यों को प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा इस मद में जानबूझ कर छुपाया गया है। माह सितम्बर 2016 की राशन सामग्री स्टॉक रजिस्टर में शेष रही है एवं वितरण की गयी है, को जांच रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया है। मात्र पोश मशीन के वितरण के आधार पर यह सारी कार्यवाही को राजनैतिकवश अंजाम दिया गया है। दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 14.05.2017 के कोई फर्दमौका पर्चा तैयार नहीं किये गये है। सारी कार्यवाही गलत रूप से तैयार की गयी है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी व अनियमितता नहीं की गयी है। प्रार्थनापत्र का मद नं. 5 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। माह सितम्बर 2016 में राशन सामग्री गेहू व केरोसीन का वितरण जिला करौली में वितरण रजिस्टर से किया गया है। जिसके तहत केरोसीन का सितम्बर 2016 का वितरण, वितरण रजिस्टर से हुआ है। जिसे मद में प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जानबूझकर दर्ज नहीं किया गया है। यदि सितम्बर 2016 के स्टॉक व वितरण रजिस्टर के तहत सामग्री को मात्रा से आंकलन कर दर्ज किया जाता तब अप्रार्थी के विक्रय कोई अनियमितता नहीं पायी जाती परन्तु राजनैतिक रंजिश के कारण इस तथ्य को छुपाकर यह गलत तथ्यों पर आवेदन पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी के विरुद्ध प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 112/2017 थाना सपोटरा धारा 3/7 ई.सी.एक्ट 'माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एसबी क्रीमिनल रिट पिटीशन न. 5871/2017 के निर्णय दिनांक 06.03.2018 से निरस्त की जा चुकी है एवं अप्रार्थी के विरुद्ध की गयी जांच रिपोर्ट दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 15.05.2017 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के सिविल रिट याचिका संख्या 12858/2017 निर्णय दिनांक 09.08.2017 से निरस्त की जा चुकी है एवं राज्य सरकार द्वारा दायर द्वितीय सिविल स्पेशल अपील मु.नं. 1647/17 दिनांक 04.12.2017 को खारिज हो चुकी है। इन समस्त निर्णयों से अप्रार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 113/17 निरस्त हो जाने से दिनांक 15.05.2017 को तैयार किया गया सुपुर्दगीनामा की समस्त सामग्री अप्रार्थी को वापस लौटाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अप्रार्थी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है तब समस्त रसद सामग्री (जब्तशुदा) अप्रार्थी के वापस लौटाई जाये। निर्णय दिनांक 09.08.2017 व 04.12.2017 की फोटो प्रति जवाब के साथ पेश की है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। राज्य सरकार द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 13.05.2017 व 14.05.

2017 अप्रार्थी श्री ग्राम पंचायत इनायती के 1/3 भाग के राशन डीलर श्री त्रिलोक चंद मीना की दुकान की जांच की गई जिसमें दुकान बंद मिलना, राशन सामग्री का टाइटल बोर्ड दुकान पर प्रदर्शित नहीं करना, माह अप्रैल 17 के राशन का वितरण नहीं करना, राशन सामग्री का निर्धारित स्थल पर भण्डारण नहीं करना आदि अनियमितताएं पाई गईं। वक्त जांच अप्रार्थी राशन डीलर की दुकान की दुकान पर सितंबर 2016 से वक्त जांच तक आपूरित गेहूं 426.25 क्विं. में से 388.30 क्विं. गेहूं के वितरण उपरांत 37.95 क्विं. गेहूं होने चाहिये थे जबकि वक्त जांच अप्रार्थी की दुकान पर 59.35 क्विं. गेहूं अधिक पाये जाकर 97.30 क्विं. गेहूं पाये गये। अप्रार्थी द्वारा 1237.5 लीटर केरोसीन का अनाधिकृत स्थल पर भण्डारण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13.05.2017 से दिनांक 15.05.2017 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के सिविल रिट याचिका संख्या 12858/2017 निर्णय दिनांक 09.08.2017 से निरस्त की जा चुकी है एवं राज्य सरकार द्वारा दायर द्वितीय सिविल स्पेशल अपील मु.नं. 1647/17 दिनांक 04.12.2017 को खारिज हो चुकी है जिसमें प्रार्थी को पुनः जांच करने की स्वतंत्रता दी गई थी। प्रार्थी द्वारा पुनः जांच कर रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, करौली को निर्देश दिये जाते हैं कि तत्कालीन रिकॉर्ड के आधार पर पुनः जांच की जावे। जांचोपरांत यदि अप्रार्थी दोषी पाया जाता है अथवा कोई अनियमितता पाई जाती है तो पुनः प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया जावे अन्यथा जब्तशुदा सामग्री को नियमानुसार पोश मशीन से वितरण करवा दिया जावे। जांच होने तक जब्तशुदा सामग्री जब्त रहेगी। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नन्मूल पहाडिया)

जिला कलक्टर

करौली